भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3980
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

कार्बन सीमा समायोजन तंत्र

3980. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात निर्यात पर यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) के संभावित प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन किया है अथवा करने का विचार है;

(ख) यूरोपीय संघ को भारतीय इस्पात निर्यात की वर्तमान रुझान का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान मात्रा के मूल्य का राज्य और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सीबीएएम द्वारा अधिदेशित कार्बन उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने में भारतीय इस्पात निर्यातकों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) भारत में कम कार्बन और हरित इस्पात विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे उपायों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) सीबीएएम और अन्य पर्यावरणीय विनियमों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के वाबजूद यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय इस्पात वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी बना रहे, कौन-कौन सी विशिष्ट पहलें की गई हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है तथा इस्पात का निर्यात वैश्विक बाजार की स्थितियों और कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (सीबीएएम) जैसी नीतियों, मांग और आपूर्ति, लौह अयस्क, कोकिंग कोल आदि जैसे इनपुट कच्चे माल की लागत जैसे कारकों पर निर्भर करता है जो बाजार से जुड़े होते हैं।

विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ (ईयू) को निर्यात किए गए तैयार इस्पात की मात्रा और मूल्य के आंकड़े निम्नलिखित है:-

यूरोपीय संघ को तैयार इस्पात का निर्यात		
वर्ष	**मात्रा (एमएनटी में)**	**मूल्य (रुपये करोड़)**
2019-20	1.95	10,692
2020-21	2.51	14,144
2021-22	3.58	32,149
2022-23	2.49	22,482
2023-24	4.03	29,534
स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी); एमएनटी=मिलियन टन; नोट: वर्ष 2020-21 तक यू.के. ईयू का हिस्सा था।		

भारत में कम कार्बन और हरित इस्पात विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:-

I. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान'' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

II. मंत्रालय ने निम्न उत्सर्जन इस्पात को परिभाषित और श्रेणीबद्ध करने हेतु मानक उपलब्ध कराने के लिए हरित इस्पात का वर्गीकरण जारी किया है।

III. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु 3 पॉयलट परियोजनाएं प्रदान की हैं।

IV. जनवरी, 2010 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

*****